3.15 करोड़ की नई सड़क बनाने से पहले लाखों का फर्जी भुगतान उठाने के लिए करवाए घटिया पेचवर्क?

अजमेर एलिवेटेड रोड पर बुधवार रात को जेडीए जोन-7 द्वारा कराए गए पेचवर्क एक रात भी नहीं टिके

अजमेर एलिवेटेड रोड पर पेचवर्क उखड़ने के बाद सड़क पर बिखरी रोडी-कंक्रीट, जो हादसों को न्यौता दे रही है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । अजमेर एलीवेटेड रोड पर घटिया पेचवर्क और दुगुने पैसे लगाकर उसे उखाड़ने में जे.डी.ए. के लाखों रुपए की बर्बादी करने के मामले में जे.डी.ए. कमिश्नर आनंदी ने वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांग ली। मजेदार बात यह है कि जेडीए जोन-7 ने अजमेर रोड एलीवेटेड रोड पर पुरानी चुंगी से मजार तक 3.15 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क बनाने के लिए टैंडर जारी किया है। यानि कि 3.15 करोड़ रुपए लगाकर सड़क की रि-कारपेटिंग की जायेगी। टैंडर की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। सफल आवेदक को वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। इस कारपेटिंग से पहले सड़क पर पुरानी डामर को उखाड़ा जाएगा। ऐसे में यह सभी पेचवर्क भी उखडेंगे, जो बरसात के दौरान किये जा रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो नई सड़क निर्माण से पहले जेडीए जोन-7 के इंजीनियर्स ने बुधवार रात आनन-फानन में यह घटिया पेचवर्क कराए, जो कुछ घंटे भी नहीं चले। यह कारनामा ठेकेदार व इंजीनियर्स ने इसलिए किया गया कि, कुछ दिनों बाद जब सड़क नई बनाई जाये, तब यह पेचवर्क उखाड़ने पडेंगे, ऐसे में चुपचाप लाखों रु. का भुगतान उठा लिया जाये।

- **यह मामला उजागर होने के बाद शुक्रवार को जे.डी.ए. कमिश्नर ने अतिरिक्त निदेशक से रिपोर्ट मांगी**
- **अजमेर रोड एलीवेटेड रोड पर पुरानी चुंगी से मजार तक सड़क निर्माण के लिए गत दिनों जारी किया है करीब 3.15 करोड़ रु. का टैंडर**

'राष्ट्रदूत' में घटिया पेचवर्क की खबर छपने के बाद शुक्रवार को जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने अतिरिक्त निदेशक संजीव जैन से इस मामले में वस्तुस्थिति से अवगत कराने और वास्तविक रिपोर्ट देने को कहा। घटिया पेचवर्क करने का मामला उजागर होते ही जोन 7 के एक्सईएन तरूण सिंघल ने अपनी अलग-अलग टीमें मामले को मैनेज करने में लगा दी।

इस बीच मामला बिगड़ता देख एक्सईएन सिंघल ने घटिया पेचवर्क के काम को छिपाने के लिए ठेकेदार खुदाबक्श से मौके पर झाड़ू लगवाने को कहा, ताकि रोड पर बिखरी रोडी-कंक्रीट नहीं दिखे।

एक करोड़ रुपए के पेचवर्क पानी में बहे

सूत्रों की मानें तो जोन-7 में मार्च माह में ही एक करोड़ रुपए पेचवर्क कराने के लिए स्वीकृत करते हुए टैंडर जारी कर दिए थे। यह टेंडर खुदाबक्श कंपनी ने हासिल किए। इसके बाद बरसात और उससे पहले ठेकेदार को पेचवर्क करने का वर्क आर्डर अगस्त तक जारी नहीं किया। सितंबर माह में अचानक जेडीए के जोन 7 के इंजीनियर्स को ध्यान आया कि इस एलीवेटेड रोड पर पेचवर्क कराना है। इसके बाद एक रात में ऐसे घटिया पेचवर्क कराए कि अगले दिन सवेरे ही बिखर गए। मामला बिगड़ता देख शुक्रवार को इन उखड़े हुए पेचवर्क पर कोल्ड डामर कराई गई, जिससे यह टाट के पैबंद जैसी यह लग रही थी। अब ठेकेदार को घटिया पेचवर्क का भुगतान करने की तैयारी की जा रही है।

सूत्रों की मानें तो जोन 7 के इंजीनियर्स को जेडीए प्रशासन की सख्ती और कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है। ऐसे में वह मौके पर जाकर पेचवर्क करने या सड़क की कारपेटिंग कराने में भी ध्यान नहीं देते। पीछे से ठेकेदार को पूरी छूट मिल जाती है और वह पेचवर्क के नाम से हल्की डामर की परत चढ़ाकर अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं।

निदेशक एक माह के अवकाश पर

सूत्रों की मानें तो जेडीए के निदेशक इंजीनियरिंग अजय गर्ग एक महीने के अवकाश पर चले गए हैं। जेडीए में चर्चा है कि नई जेडीए कमिश्नर से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। उनकी नाराजगी से बचने के लिए निदेशक एक महीने के अवकाश पर चले गए। उनका कार्यभार अतिरिक्त चीफ इंजीनियर संजीव जैन को सौंपा गया है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में प्रदेशभर में लगाए जाएंगे कैंप

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा गौ-पालक परिवारों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरु की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की क्रियान्विति के लिये राज्यभर में अगले सप्ताह से एक पखवाड़े तक कैम्प लगेंगे। योजना में पात्र गोपालको को एक वर्ष की अवधि के लिये एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आगामी 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर डेयरी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंक (पैक्स) के संयुक्त कैम्पों में गोपालको से ऑनलाईन आवेदन लिये जाएंगे।

- **गौ-पालकों को एक वर्ष की अवधि के लिये एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा**

यह जानकारी देते हुए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में गोपालको को डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गौवंश हेतु शैड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांट के उपकरण खरीदने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट योजना की क्रियान्विति की जा रही है।

प्रथम चरण में 5 लाख गौ-पालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे, और इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि गोपालको को ऋण के लिये ऑनलाईन आवेदन हेतु राज्यभर के जिला दुग्ध संघों को पैक्स बैंक के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर कैम्प आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दूध का बेचान करता हो, को प्राथमिक दुग्ध समिति की अनुशंषा पर ऋण प्राप्त कर सकता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु गोपालक से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जावेगा। गोपालक द्वारा समय पर अथवा समय से पूर्व चुकारा किये जाने पर आगामी एक वर्ष के लिये नवीन ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर के दौरान गोपालक संयुक्त शिविरों में आसानी से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।

सार-समाचार

आई.सी.आई.सी.आई. पेंशन प्लान लॉंच

जयपुर । आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में "आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर पेंशन" प्लान लॉन्च किया है, जो पॉलिसी होल्डर्स को रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन फंड बनाने में मदद करता है। पेंशन प्लान के साथ ही कंपनी ने दो नए फंड्स - पेंशन इंडिया ग्रोथ और पेंशन बैलेंस्ड फंड भी लॉन्च किए हैं, जिससे ग्राहकों के फंड को और बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर अमित पाल्टा ने कहा कि यह प्रोडक्ट हमारे ग्राहकों को उनका रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे और साथ ही भारत के विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। इस पेंशन प्लान की खासियत यह है कि आप रिटायरमेंट के बाद 60 प्रतिशत तक का फंड बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं। साथ ही, अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है, तो पॉलिसी होल्डर्स आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर्स को पास अपनी आय शुरू करने के लिए दो विकल्प मिलेंगे। रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद में। गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में भी ग्राहक अपनी पेंशन योजना जारी रह सकती है, जिससे रिटायरमेंट योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पेंशन प्लान पॉलिसी होल्डर्स को बिना किसी परेशानी के अपनी रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने का मौका देता है।

मेट्रो कर्मचारियों को दिलाई शपथ

जयपुर । जयपुर मेट्रो में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक "स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024" स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने बताया कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य न केवल शहर को स्वच्छ बनाना है, बल्कि सभी नागरिकों के भीतर स्वच्छता को एक आदत के रूप में स्थापित करना भी है। इस अभियान के तहत जयपुर मेट्रो के मानसरोवर मेट्रो डिपो में सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गयी। अभियान के दौरान मेट्रो परिसर में सफाई के साथ-साथ स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, श्रमदान कार्यक्रम, पौधारोपण, कार्यालयों का निरीक्षण कर ब्लैक स्पॉट समाप्त करना, जागरूकता संदेशो का प्रचार-प्रसार करने संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

राज्य कर्मचारियों ने मनाया ज्ञापन दिवस

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर की गई घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को हजारों राज्य कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिवस मनाया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रस्तुत किया। राजधानी जयपुर में यह ज्ञापन महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ व जिला अध्यक्ष छोटेलाल मीणा की अगुवाई में गए एक शिष्ट मंडल ने मुख्य सचिव को सौंपा। वार्ता में मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में वित्त विभाग से जानकारी ली जाएगी और अन्य मांगों पर वित्त विभाग स्तर पर वार्ता आयोजित कराई जाएगी। महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई 2024 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की शेष सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। इससे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में काफी आक्रोश है।

कोल्ड स्टोरेज पर 1.40 करोड़ तक अनुदान

जयपुर । कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषक उद्यमी या कृषक समूह को कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अधिकतम 1 करोड़ 40 रुपये तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता 4 अक्टूबर तक सम्बन्धित जिले के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में आवेदन कर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। गालरिया ने पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज पर राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजनान्तर्गत 250 मेट्रिक टन से लेकर अधिकतम 5 हजार मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। कोल्ड स्टोरेज बनाने पर इकाई लागत का 8 हजार रूपये प्रति मेट्रिक टन से गणना कर अधिकतम 5 हजार मेट्रिक टन पर इकाई लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ 40 लाख रूपये का अनुदान दिया जाता है।

स्मैक-गांजा तस्कर गिरफ्तार

जयपुर । जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत चौमू और सिंधी कैंप थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए स्मैक और गांजा की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25.77 ग्राम स्मैक, 15 किलो 900 ग्राम गांजा सहित परिवहन में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अरशद अली ने बताया कि सीएसटी ने चौमू और सिंधी कैंप थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए स्मैक और गांजा की तस्करी करने वाले बाबुलाल स्वामी निवासी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना और उदय कुमार यादव निवासी नानपुर जिला सीतामढ़ी(बिहार) को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पुलिस ने 25 ग्राम 77 मिलीग्राम स्मैक,15 किलो 900 ग्राम गांजा सहित परिवहन में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन जब्त किया है।

एक चिकित्सक का पंजीयन निरस्त, 9 को कड़ी चेतावनी

राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक में निर्णय

जयपुर (कासं)। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक शुक्रवार को निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज से मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया।

निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि बैठक में पैनल एंड एथिकल कमेटी के समक्ष कुल 17 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। जिसमें एनएमसी, दिल्ली के दिशा-निर्देश अनुसार 1 चिकित्सक का पंजीयन निरस्त किया गया एवं 9 चिकित्सकों को चेतावनी जारी की गई। उन्होंने बताया कि फर्जी दस्तावेज लगाए जाने के कारण डॉ. राहुल वर्मा का पंजीयन निरस्त किया गया है। रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के समस्त रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने, चिकित्सकों के क्रेडिट अवार्ड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सीएमई सिस्टम लागू करने एवं परिषद में पंजीकृत चिकित्सकों का क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रगति की भी बैठक में समीक्षा की गई। डॉ. शर्मा ने बताया कि काउंसिल के काम को गति देने एवं सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से वेबसाइट को अद्यतन किया गया है। साथ ही, कार्य को अधिक सुगम बनाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग भी किया जाएगा।

बी.एस.एन.एल. में 'नैतिकता-शासन' सेमीनार

जयपुर । राजस्थान बी.एस.एन.एल. परिमंडल की विजिलेंस सेल ने शुक्रवार को कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जयपुर के कांफ्रेंस हॉल में नैतिकता एवं शासन सेमीनार आयोजित किया। महाप्रबंधक (सतर्कता) दिनेश कुमार गर्ग ने सभी अधिकारियों, अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में बताया। सेमीनार का उद्घाटन बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने किया। सेमीनार के मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्व आईएएस अधिकारी एस.एस.बिस्सा थे।

राजस्थान बी.एस.एन.एल. परिमंडल की विजिलेंस सेल ने शुक्रवार को नैतिकता एवं शासन विषय पर सेमीनार आयोजित किया।

बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने अपने उदबोधन में नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने पर प्रकाश डाला तथा तथा उत्तम व्यवहार एवं सदाचार को जीवन में अपनाने के लिए कहा। साथ ही, प्रशासन में पारदर्शिता अपनाने पर भी बल दिया। मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्व आईएएस अधिकारी एस.एस.बिस्सा ने अपने व्याख्यान की शुरुआत ऋग्वेद के एक श्लोक से की तथा नैतिकता एवं शासन विषय पर प्रकाश डालते हुए आपने पारदर्शिता, जन सहभागिता एवं विधि के शासन की जरूरत बताई।

कार्यक्रम में प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जयपुर राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ महाप्रबंधक (प्रशासन एवं एच आर) अखलेश अग्रवाल, महाप्रबंधक (सेल्स एण्ड मार्केटिंग) एल.एस.मीना, महाप्रबंधक सीएम अशोक माहेश्वरी, महाप्रबंधक (मुख्यालय) निधि माथुर, महाप्रबंधक (ईबी) उपेन्द्र बाकोलिया, महाप्रबंधक (नोफ़न) सुभाष चंद्र अग्रवाल, महाप्रबंधक लोकेश गुप्ता, महाप्रबंधक वीएस नेमीवाल, सहित बीएसएनएल के कई वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उप मण्डल अभियंता राजभाषा डॉक्टर सीमा गुप्ता ने किया। सहायक निदेशक सतर्कता मनीष अग्रवाल ने सभी अधिकारियों, अतिथियों व प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

अगले 45 दिन में साफ करेंगे द्रव्यवती नदी : वैभव गालरिया

जयपुर । राजधानी जयपुर के बीचों बीच बहने वाली द्रव्यवती नदी को अगले 45 दिनों में साफ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया द्रव्यवती नदी का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने जेडीए और निगम अधिकारियों को नदी में बह रहे सीवरेज के पानी को रोकने के साथ ही बदहाल और बदबूदार हो चुकी नदी को अगले 45 दिन में स्वच्छ और सुंदर बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जयपुर शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर काम शुरू कर किया जा चुका है।

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने शुक्रवार को द्रव्यवती नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर इसकी सफाई के निर्देश दिए।

गालरिया ने कहा कि द्रव्यवती नदी में सुशीलपुरा के नजदीक सीवरेज का पानी आ रहा है। जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना था, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर कोर्ट स्टे लेकर आ गए हैं। ऐसे में हमारे वकील कोर्ट में मजबूती से इस मामले को रखेंगे, ताकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जल्द से जल्द निर्माण होकर द्रव्यवती में जाने वाले सीवरेज के पानी को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान द्रव्यवती नदी के आसपास काफी कॉलोनी में पानी भर जाता है, जिसे रोकने के लिए पानी को द्रव्यवती में आने दिया जाता है। ऐसे में पानी के साथ गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ भी नदी में पहुंच रहे हैं। इसे रोकने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के एक्सपर्ट इंजीनियर जल्द ही ठोस रणनीति के तहत काम करेंगे। इसका असर जल भविष्य में नजर आएगा। जो पानी फिलहाल द्रव्यवती नदी में बह रहा है, वह भी काफी गंदा और बदबूदार है। ऐसे में अगले 45 दिनों में इस द्रव्यवती नदी में बहने वाले पानी को साफ किया जाएगा। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर तीनों के अधिकारी मिलकर एक्शन प्लान के तहत काम करेंगे। जिसमें न सिर्फ सीवरेज के पानी को साफ करेंगे। बल्कि, द्रव्यवती नदी के वाक-वे में ग्रीनरी और लाइट पोल समेत तमाम मेंटेनेंस के काम को भी दुरुस्त किया जाएगा। गालरिया ने कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जयपुर की सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस बार जयपुर में काफी ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से सड़कों की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे शहर में सड़कों का नवीनीकरण व मरम्मत कराएंगे।

वृत्त कार्यालयों में बनाएं हैल्प डेस्क

जयपुर । डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने आमजन व बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जयपुर शहर एवं जयपुर जिला वृत्त के अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में हैल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन हैल्प डेस्क के माध्यम से बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आमजन को पूरी संवेदनशीलता से परामर्श प्रदान किया जाए। डोगरा शुक्रवार को विद्युत भवन में जयपुर सिटी एवं जयपुर जिला सर्किल के वृत्त अधीक्षण अभियंताओं के साथ इस संबंध में समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अपनी समस्याओं तथा सुनवाई को लेकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में हैल्प डेस्क से दिया गया उचित परामर्श एवं सुझाव उन्हें राहत देगा। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने कहा कि इन हैल्प डेस्क में ऐसे कार्मिकों को पदस्थापित किया जाए जो परिवादियों की परेशानी एवं जरूरत को समझ कर उन्हें मानवीय नजरिए से समुचित सलाह दे सकें। इन कार्मिकों को सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाए।

सिंगल सुपर फॉस्फेट व एन.पी.के. का उपयोग करें किसान : चिन्मयी गोपाल

जयपुर । कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में उर्वरकों की मांग, आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण के सम्बन्ध में जिलों के विभागीय अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। उन्होंने कृषकों द्वारा डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके को अधिकाधिक उपयोग में लेने के लिए एवं विभागीय अधिकारियों को इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा।

- **'यूरिया-डीएपी के साथ टैगिंग कर अन्य उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही'**

कृषि आयुक्त ने बताया कि राज्य में इस वर्ष अच्छा मानसून होने से रबी फसलों की बुआई का क्षेत्र बढ़ने के कारण उर्वरकों की अतिरिक्त मांग सृजित होगी। राज्य में बुआई के समय उपयोग होने वाले उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं एवं किसानों की मांग के अनुरूप समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

कृषि आयुक्त ने कहा कि उर्वरक आपूर्तिकर्ता कम्पनियों एवं विक्रेताओं द्वारा यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नही की जाये तथा सभी उर्वरक विक्रेता अपने पास उपलब्ध उर्वरकों का स्टॉक मात्रा एवं मूल्य सूची प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एफसीओ, 1985 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। चिन्मयी गोपाल ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले के उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक का पीओएस स्टॉक से मिलान कर भौतिक सत्यापन करें। उर्वरक आपूर्तिकर्ता फर्मो के जिला प्रतिनिधियों से समन्वय कर सम्पूर्ण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार समान रूप से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरकों की कहीं भी कोई कालाबाजारी तथा जमाखोरी नही हो। जिले में उर्वरकों के वितरण पर सतत् निगरानी रखते हुए जिले के कृषकों को ही उर्वरकों का वितरण करें एवं राज्य के बोर्डर एरिया से उर्वरकों का परिगमन होने से रोके।

अवैध हथियार समेत तीन बदमाश गिरफ्तार

जयपुर । जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत झोटवाड़ा इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से एक देशी कट्टा और परिवहन में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि सीएसटी ने ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन के तहत झोटवाड़ा इलाके में कार्रवाई करते हुए रविन्द्र नायक जवाजा जिला ब्यावर हाल झोटवाडा, जितु भाटी उर्फ जितेन्द्र सिंह निवासी ब्यावर हाल झोटवाड़ा जयपुर और असलम काठत निवासी ब्यावर हाल झोटवाड़ा जयपुर को गिरफ्तार कर उनके पास से एक देशी कट्टा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित चोरी करने के आदि है और रात के समय चोरी करते समय लोगों की जाग जाने के कारण यह हथियार उनको डराने के लिए रखते है। आरोपित जितु और रविन्द्र के खिलाफ चोरी,नकबजनी,डकैती और मारपीट के दर्जनों मामले दर्ज है। इसके अलावा आरोपियों से चोरी का माल भी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त सहित अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

साइबर सुरक्षा की एडवाइजरी जारी

जयपुर । सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने साइबर सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूपीआई फिशिंग धोखाधड़ी व ऑनलाईन नौकरी धोखाधड़ी के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।

गृह विभाग की संयुक्त शासन सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, एससीआरबी एवं तकनीकी सेवाएं को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि बैंकिंग संबंधी मुद्दों में मदद के बहाने जालसाल पीड़ितों से उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर लिंक अग्रेषित करने के लिए कहते हैं और पीड़ित के बैंक खातों तक पहुंच जाते है। धोखेबाज लोग केवाईसी/आधार अपडेट करने के बहाने से भी ओटीपी साझा करने की कहकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। स्वयं को बैंक अधिकारी बताने वाले किसी भी व्यक्ति को ओटीपी या लिंक साझा न करें। रिफंड पाने आदि के लिए गूगल सर्च से प्राप्त कस्टमर केयर नम्बर पर कॉल करने वाले लोग इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार बन सकते है। इसके अतिरिक्त नौकरी की तलाश में अपना डेटा विभिन्न वेबसाइटों पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने वाले उपयोगकर्ता के डेटा का उपयोग साइबर अपराधी अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर पंजीकरण एवं सेवा शुल्क की मांग करते है। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए अपना आवेदन पंजीकृत वेबवाईट पर ही जमा कराएं।

- **गृह विभाग ने इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए डी.जी.पी. साइबर क्राइम, एससीआरबी को पत्र लिखा है।**

बचाव के लिए सामान्य जागरूकता टिप्स

- **ऐसे संकेतों पर ध्यान दें कि आपको कोई संदिग्ध ईमेल मिला है, जैसे ईमेल भेजने वाला, विषय, हस्ताक्षर। किसी ईमेल पर तुरत भरोसा न करें, ध्यान से पढ़े और फिशिंग संकेतों की जाँच करें। जब तक लिंक किसी विश्वसनीय स्त्रोत से न हों, तब तक उन पर क्लिक करने से बचें।**
- **अगर किसी ऐसे नंबर से टेक्स्ट मिलता है जिसे पहचानते नहीं है तो उसे ध्यान से पढ़ें। अगर स्मिशिंग टेक्स्ट मैसेज मिला है, तो उसका जवाब न दें। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति या असुरक्षित साइट को व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी न दे जिसे आप नहीं जानते। अगर मैसेज/कॉल में किसी तरह की अत्यावश्यकता की भावना हो, तो हमेशा संदेह करें। फोन कॉल के दौरान सतर्क रहें और ध्यान दे।**
- **व्यक्तिगत रूप से या फोन पर जानकारी माँगने वालों की पहचान सत्यापित करें। फोन कॉल पर अपने बैंक खाते का विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी आदि साझा न करें। क्योंकि इससे साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय हो सकती है, जिससे पैसे की हेराफेरी हो सकती है। अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें। एंटीवायरस इंस्टॉल करें और नियमित रूप से अपडेट करें।**